संख्या-296/2024/1315/35-4-2024/35-4099/259/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जालौन।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 25 नवम्बर, 2024

विषय:- जनपद जालौन में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत कार्य की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद जालौन में वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या-347/2021/2196/35-4-2021, दिनांक 04 दिसम्बर,2021 द्वारा 05 स्वीकृत निर्माण कार्यों में से प्रश्नगत कार्य (शासनादेश दिनांक 04 दिसम्बर,2021 के क्रमांक-04 पर अंकित) हेतु अनुमोदित लागत रू0 30.20 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 15.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- जिलाधिकारी, जालौन के पत्र सं0-217/त्वा0आ0वि0यो0/ 2024-25 दिनांक 30 जुलाई, 2024 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि का उपभोग किया जाना इंगित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 15.20 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि के रूप में **रू0 15.20 लाख (रूपये पन्द्रह लाख बीस हजार मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपए लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
वि0ख0 कदौरा के ग्राम चन्दरसी में विक्रम राजपूत मकान से चेता कोरी तक सी0सी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	30.20	15.00	15.20

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04 दिसम्बर,2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि **रू0 15.20 लाख (रूपये पन्द्रह लाख बीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखा शीर्ष-505404337030303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों केलिए एक मुश्त व्यवस्था मानक मद 24- वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

संख्या-296/2024/1315(1)/35-4-2024/35-4099/259/2021तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जीउ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, झाँसी मण्डल।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, जालौन।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जालौन ।
13. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जालौन ।
14. नोडेल अधिकारी, बजट आबंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।